# पर्ल
## आज तक
### जे.एन.एन.यू.आर.एम. का प्रयास

सितम्बर 2009

एस.ए.टी.आई.एस. परियोजना, जे.एन.एन.यू.आर.एम., ठाणे नगर निगम, महाराष्ट्र

## विषय सूची


मेगा शहरों (मेगा सिटीज) पर राष्ट्रीय कार्यशाला

मेगा शहर तथा शहरी सुधार

श्रेष्ठ कार्यों का प्रलेखन

पर्ल वेबसाइट पर नवीनतम सूचनाएं

जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शामिल शहरों को कार्य-प्रदर्शन पुरस्कार

जे.एन.एन.यू.आर.एम प्रवेशिकाएं

शहरी प्रयासों से संबंधित जानकारी मांगना।


शहरी विकास मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण अभियान में शामिल शहरों के परस्पर संपर्क के लिए एक मंच तैयार किया जो पीयर एक्सपीरियेन्स एण्ड रिफ्लेक्टिव लर्निंग (पर्ल) के नाम से जाना जाता है। ऐसा शहरी सुधारों व शहरी शासन पर अध्ययन व ज्ञान बांटने के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शामिल शहरों के मध्य प्रबंधनीय नेटवर्क का निर्माण करने के लिए किया गया।

## मेगा शहरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत पर्ल कार्यक्रम की गतिविधि के रुप में रा.न.का.सं. में, नई दिल्ली में 4 जुलाई 2009 को मेगा शहरों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहरी विकास मंत्रालय, कोलकात्ता नगर निगम, वृहन्न मुम्बई (ग्रेटर मुम्बई) नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों सहित मेगा सिटीज़ एसोसिएशन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इनवायरमेंट एनीशिएटिव (आई.सी.एल.ई.आई.), जल एवं सफाई-व्यवस्था कार्यक्रम, इंटरनेशनल सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन (आई.सी.एम.ए.) सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन कर्नाटक (सी.एम.ए.के.), सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन गुजरात (सी.एम.ए.जी), अर्बन मैनेजमेंट सेंटर (यू.एम.सी.), सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नॉलोजी (सी.ई.पी.टी.), रा.न.का.सं. आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शहरी सुधारों, पी.पी.पी. तथा मेगा सिटीज समूह से संबंधित शहरों में हुए नवीन कार्यो पर चर्चा करना था।

प्रो. चेतन वैद्य, निदेशक, रा.न.का.सं. ने भागीदारों का स्वागत किया तथा पर्ल कार्यक्रम के उद्देश्य दृष्टिकोण तथा कार्यपद्धति पर प्रकाश डाला। श्री आलापान बंदोपाध्याय, आई.ए.एस., आयुक्त, के.एम.सी. ने भी भागीदारों का स्वागत किया, एम.सी.ए. के गठन का पता लगाया तथा इसकी गतिविधियों पर चर्चा की।

श्री पी.के. श्रीवास्तव, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, जे.एन.एन.यू.आर.एम ने अपने मुख्य अभिभाषण में उच्च स्तर पर शहरों के बीच परस्पर बातचीत तथा उनमें आपस में एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

श्री श्रीवास्तव ने मेगा सिटीज द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) और सुधारों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तीव्र करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उन 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां मेगा सिटीज और कार्य कर सकते हैं (क) वित्तीय बाजार से धन की व्यवस्था करना; (ख) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.); (ग) स्वच्छ विकास तंत्र; तथा (घ) शहरी परिवहन। इस अवसर पर उन्होंने 7 मेगा-सिटीज द्वारा किए गए नवीन कार्यो पर एक सूची-पत्र (केटालॉग) (एम.सी.ए. द्वारा प्रलेखित) जारी किया जिसका शीर्षक था ''मेगा सिटीज ऑन रिफोमर्सः ए केटेलॉग ऑन इनोवेटिव प्रेक्टिसिस 2009''।

प्रो. वी.के.धर, रा.न.का.सं. नं पर्ल की गतिविधियो की समीक्षा पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने ज्ञान-बांटने और एक-दूसरे से सीखने के क्षेत्र में हुई प्रगति के विषय में www.indiaurbanportal.in तथा ''पर्ल आजतक'' न्यूजलैटर के माध्यम से भागीदारों को अवगत कराया। इस अवसर पर, पर्ल के अंतर्गत संस्थान द्वारा तैयार ''डाक्यूमेंटेशन ऑफ दि बेस्ट प्रेक्टिसिस'' के प्रथम खण्ड को भागीदारों के बीच परिचालित किया।

श्री प्रकाश कुमार, निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र, आई.बी.एस.जी., सी.आई.एस.सी.ओ ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा शहरी शासन में सहयोग की महत्ता पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने पर्ल पोर्टल को प्रभावशाली बनाने के लिए एक जीवंत मंच के रुप में इसे कायम रखने के विचार को व्यक्त किया।

शहरी सुधारों और पी.पी.पी. पर अंतिम सत्र में चार शहरों कोलकाता, मुम्बई, अहमदाबाद तथा नई दिल्ली के प्रस्तुतीकरण देखें। शहरों के प्रतिनिधियों ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. सुधारों की

स्थिति तथा संबंधित शहरों में इस संबंध में किए गए नवीन प्रयासों पर चर्चा की।

श्री एस. इस्लाम, आई.ए.एस. संयुक्त नगर निगम आयुक्त, के.एम.सी. ने नगर-निगम सेवाएं प्रदान करने के स्तर को उच्च करने के लिए के.एम.सी. द्वारा 2003 में आरंभ किया गया ''क्षमता-निर्माण कार्यक्रम-कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम-सी.बी.पी.'' के विषय में बताया। सी.बी.पी को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करना अपेक्षित हैः (क) संगठनात्मक विकास; (ख) जन-संपर्क तथा संप्रेषण; (ग) भौगालिक सूचना प्रणाली; (घ) कार्यक्रम प्रबंधन तथा; (ड़) संसाधन जुटाव तथा उन्नत वित्तीय प्रबंधन।

श्री राजेन्द्र वाले, नगर निगम उपायुक्त, एम.सी.जी.एम. ने मुम्बई शहर में सुधारों की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने एम.सी.जी.एम.के, ई. - शासन संबंधित प्रयासों, ठोस कचरा निपटान हेतु जी.पी.एस. आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली तथा शहर में पुराने भवनों के पुनर्विकास के लिए पी.पी.पी. मॉडल पर प्रकाश डाला।

श्री एम.एस.पटेल, नगर निगम उपायुक्त, ए.एम.सी. ने शहर में संपत्ति कर, प्रयोक्ता शुल्क, ई-गवर्नेस, वित्तीय प्रबंधन, लेखाकरण सुधारों, जन-प्रकटन, शहरी गरीबों के लिए सेवाएं, निजी सार्वजनिक भागीदारी आदि क्षेत्रों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. सुधारों का कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई।

श्री मनीष कुमार, वित्तीय सलाहकार, एन.डी.एम.सी. ने ई.-गवर्नेंस में लेखाकरण सुधारों पर ''एन.डी.एम.सी. में ई.-वित्त'' नामक शीर्षक से एक केस-अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने एन.डी.एम.सी. में लेखाकरण सुधारों पर व्याख्यान देते हुए ई-शासन के प्रयोग पर चर्चा की।

बैठक के मुख्य परिणाम निम्नलिखित थेः

- सुधार कार्यसूची में ई-शासन की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए तथा पर्ल मंच को ज्ञान तथा सूचना बांटने के लिए उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है;
- मेगा शहरों को अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने तथा स्वयं को स्वतः कायम रखने के लिए पूंजी-बाजार तक पहुंचाने के लिए मार्ग खोजना चाहिए;
- मेगा शहरों के आम-मुद्दों पर ध्यान देने व उनको पहचानने के लिए शहरों के बीच कार्य-दल के गठन की संभावना का पता लगाना, इन मुद्दों पर काम करना तथा उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करना। ऐसे समाधानों को पर्ल नेटवर्क के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इन कार्यदलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संगठनों, दानी ऐजेन्सियों आदि से विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है।

अंत में प्रो. वैद्य ने विचार-विमर्श का संक्षेप किया तथा समस्त भागीदारों को धन्यवाद दिया।

## मेगा शहर और शहरी सुधार

### के.एम.सी. के क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रभावः

नगरपालिका सेवाओं को प्रदान करने के मानकों को बढ़ाने के लिए कोलकाता नगर निगम ने वर्ष 2003 में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, ब्रिटेन सरकार, ने इस परियोजना को वर्ष 2003 से 6 वर्ष की अवधि के लिए वित्त-पोषण दिया। परिणाम स्वरुप, नगर-विकास, सामाजिक-क्षेत्र तथा पी.पी.पी. सेल, नागरिक-केन्द्रित प्रक्रिया जैस नए विभागों का निर्माण किया गया तथा सेवा-प्रदान करने के लिए जवाबदेही में वृद्धि हुई। ई-शासन के क्षेत्र में नगर-निगम प्रशासन के अंतर्गत 4 ई-कोलकाता नागरिक सेवा केन्द्रों को प्रचालित किया गया, 25 विभागों को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा जी.आई.एस. का कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

### वर्ग IV के कार्मिकों की भर्ती के लिए एम.सी.जी.एम. की नवीन पद्धति

वर्ग IV के कार्मिकों की भर्ती के लिए एम.सी.जी.एम के नवीन प्रयास ग्रेटर मुम्बई नगर निगम ने वर्ग IV के कार्मिकों की भर्ती के लिए तत्काल-चयन (वॉक-इन सलेक्शन) की एक अद्वितीय प्रक्रिया का आरंभ किया। इसके अंतर्गत रिक्त पदों के लिए समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में विज्ञापन दिया गया। संबंधित रोजगार कार्यालयों (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज) में भी अधिसूचना भेजी गई। अधिकतर पदों हेतु चयन का कार्य भर्ती के दिन ही संपूर्ण हो गया था। इस भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच, योग्य व्यक्तियों की पहचान, चयनित उम्मीदवार की योग्यता सूची (श्रेणीवार/जाति के अनुसार) की घोषणा, उम्मीदवारों को चिकित्सीय-जांच एवं पुलिस-सत्यापन के लिए निर्देश देना तथा संबंधित विभागों के रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियुक्ति हेतु भेजना शामिल है। इस प्रक्रिया को आरंभ करने से, भर्ती के लिए लगने वाले आवश्यक समय में बहुत कमी आई। यह संपूर्ण प्रक्रिया उम्मीदवार के साथ-साथ प्रशासन के लिए पारदर्शी व किफायती है।

### अहमदाबाद ने गरीबों के हित में सुधारों के लिए मार्ग दिखाया

अहमदाबाद जे.एन.एन.यू.आर.एम. सुधारों के कार्यान्वयन में अग्रणी रहा। इसमें शहरी गरीबों के लिए योजनाएं विशेष रुप से उल्लेखनीय है। ए.एम.सी. ने स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। ए.एम.सी. ने दर्शाया कि भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से स्लम में काफी सुधार हो सकता है। इसके अंतर्गत ए.एम.सी. के 'उम्मीद' प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्लम उन्नयन के माध्यम से शहरी गरीबों के विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, परियोजना से प्रभावित गरीब परिवारों के पुनर्वास, गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के कौशल उन्नयन पर कार्य किया गया।

## लेखाकरण–सुधारों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एन.डी.एम.सी. ने ई–शासन का प्रयोग किया

नई दिल्ली नगर पालिका ने वास्तविक प्रबंधन सूचना पद्धति की आवश्यकता अनुभव की तथा लेखाकरण सुधारों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय लेखाकरण पैकेज विकसित करने का निर्णय लिया जो कि राष्ट्रीय लेखाकरण मार्गनिर्देशों के पूर्णतया अनुरुप होगा। एन.डी.एम.सी. ने ई–शासन फाउंडेशन के साथ अनुबंध किया। परिणामस्वरुप, एक लचीला कोडीकरण ढांचा क्रियान्वित किया गया था। ई–शासन वित्तीय लेखाकरण प्रणाली में विभिन्न पहलू जैसे खाता, स्थायी संपत्ति प्रबंधन, वित्त आधारित लेखाकरण, बजट, बैंक प्रबंधन, रिपोर्टिंग (संवैधानिक तथा लेखाकरण रिपोर्ट) तथा संपत्ति कर एकीकरण शामिल है।

## ''श्रेष्ठ कार्यों का प्रलेखन''

'पर्ल' के अंतर्गत 'श्रेष्ठ कार्यों का प्रलेखन' नामक प्रकाशन को श्रेष्ठ कार्यों के प्रलेखन के लिए डिजाईन किया गया। श्रेष्ठ कार्यों के केस अध्ययन को पर्ल वेबसाइट में इण्डिया अर्बन पोर्टल के डेटाबेस से लिया गया है। प्रत्येक केस अध्ययन संक्षिप्त सारांश, प्रमुख तिथियां, प्रयास से पूर्व की स्थिति, प्रयासों को विकसित करने की कार्यनीति, प्रक्रिया, प्राप्त परिणाम, सततता, प्राप्त अनुभव, मान्यता तथा पुनरावृत्ति को प्रस्तुत करता है। ये दस्तावेज पीयर नेटवर्किंग के भाग के रुप में तथा अभियान में शामिल शहरों के बीच सीखने के लिए तैयार किए गए। श्रेष्ठ कार्यों में श्रेणियों के क्रास–सेक्शन जैसे क्षेत्र/सेवाएं (जल–आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज/जल–निकासी, सड़कें/फ्लाईओवर तथा जन–परिवहन प्रणाली), शहरी गरीबी, आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण शामिल है।

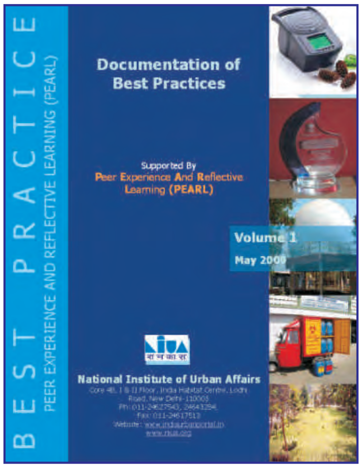


श्रेष्ठ कार्यों का विवरण www.indiaurbanportal.in पर भी उपलब्ध है।

रिपोर्ट में निम्नलिखित श्रेष्ठ कार्यों को शामिल किया गया है:

- जल–आपूर्ति प्रणाली में प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य: सूरत, गुजरात;
- जल गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली: सूरत, गुजरात;
- 24x7 जल आपूर्ति परियोजना: नागपुर, महाराष्ट्र;
- बी.ओ.ओ.टी. पर आधारित केन्द्रीकृत जैव–चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की स्थापना: सूरत, गुजरात;
- सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कचरा प्रसंस्करण संयंत्र: राजकोट, गुजरात;
- घर–घर जाकर कचरा एकत्रीकरण प्रणाली, सूरत, गुजरात;
- उन्नत मोहल्ला प्रबंधन कार्यक्रम; ग्रेटर मुम्बई, महाराष्ट्र;
- सीवरेज गैस से हरित ऊर्जा उत्पन्न करना; सूरत, गुजरात;
- एकीकृत सीवरेज प्रणाली हेतु अंतर–सरकारी कनवर्जन्स प्रणाली; भुवनेश्वर, उड़ीसा;
- शहरी झील जल में सुधार के लिए घरेलू सीवरेज का परिवर्तन: भोपाल, मध्यप्रदेश;
- स्ट्रीट लाइटिंग और ऊर्जा संरक्षण हेतु पी.पी.पी. ; बैंगलोर, कर्नाटक;
- फुटपाथ निर्माण में नवीन तकनीकें: बैंगलोर, कर्नाटक;
- स्ट्रीट लाईटिंग में पी.पी.पी.: विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश;
- स्टेशन के क्षेत्र में यातायात में सुधार; पुणे, महाराष्ट्र;
- सूरत में पी.पी.पी. पर आधारित सिटी बस सेवा; सूरत, गुजरात;
- दत्तक वास्ती योजना (स्लम अंगीकरण योजना): मुम्बई, महाराष्ट्र;
- कर्नाटक के शहरी स्थानीय निकायों में लेखाकरण सुधार; यू.एल.बी., कर्नाटक,
- अहमदाबाद संपत्ति कर सुधार: अहमदाबाद, गुजरात;
- आपातकालीन प्रचालन केन्द्र: मुम्बई, महाराष्ट्र, और
- जल निकायों में मूर्ति विसर्जन गतिविधियां तथा उनका प्रबंधन, भोपाल, मध्यप्रदेश

## पर्ल वेब पर नवीनतम समाचार

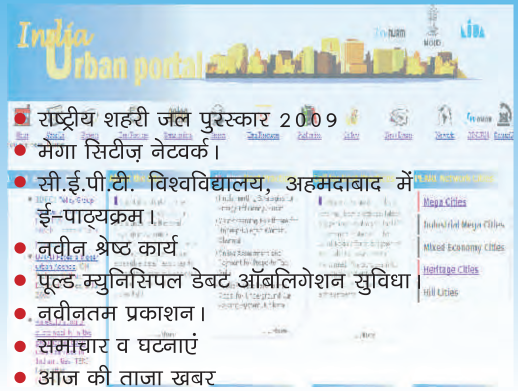


- राष्ट्रीय शहरी जल पुरस्कार 2009
- मेगा सिटीज़ नेटवर्क।
- सी.ई.पी.टी. विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में ई–पाठ्यक्रम।
- नवीन श्रेष्ठ कार्य
- पूल्ड म्युनिसिपल डेबट ऑबलिगेशन सुविधा।
- नवीनतम प्रकाशन।
- समाचार व घटनाएं
- आज की ताजा खबर

## जे.एन.एन.यू.आर.एम में शामिल शहरों को कार्य प्रदर्शन पुरस्कार 2009

श.वि.मं. ने उन शहरों के लिए पुरस्कार स्थापित किया जिन्होंने शहरी सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन में सुधार का प्रदर्शन किया। इस पुरस्कार को जारी रखते हुए, श.वि.मं. ने अभियान में शामिल शहरों द्वारा वर्ष 2009 में निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदर्शित सुधारों के लिए उनको सम्मानित करने का विचार बनाया; (1) मूल-सेवाओं में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने पर; (2) वित्तीय स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने पर और (3) पर्यावरणीय प्रयासों का लक्ष्य प्राप्त करने पर। श.वि.मं. ने इन श्रेणियों के अंतर्गत 6 क्षेत्र पुरस्कारों का प्रस्ताव दिया। प्रत्येक क्षेत्र पुरस्कार में दो शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव हैं – एक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के लिए है तथा एक पुरस्कार द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले शहर के लिए हैं। पुरस्कारों के लिए श्रेणियां निम्नलिखित है :-

| श्रेणी | पुरस्कारों के लिए श्रेणियां |
|---|---|
| मूल सेवाएं | क) जल आपूर्ति<br>ख) अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा जल-निकासी<br>ग) ठोस कचरा प्रबंधन |
| वित्तीय स्थिरता | क) वित्तीय प्रबंधन<br>ख) सुधारों का कार्यान्वयन |
| पर्यावरण | क) पर्यावरणीय प्रयास |

लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा निष्पक्ष मूल्यांकन के विचार से श.वि.मं. ने मूल्यांकन तथा पुरस्कार के पात्र शहरों के चयन के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशिष्ट कार्य निष्पादन संकेतक के विषय में आंकड़े एकत्रित करने के उद्देश्य से एक प्रोफार्मा विकसित किया गया तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शामिल समस्त शहरों को परिचालित किया गया।

### शहरी प्रयासों की जानकारी की मांग

'पर्ल आज तक' विभिन्न राज्यों अथवा शहरी स्थानीय निकायों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. से संबंधित शहरी सुधारों, श्रेष्ठ कार्यों, नवीन गतिविधियों के प्रयासों के योगदान की जानकारी का पत्रिका में प्रकाशन हेतु स्वागत करता है। अपनी प्रविष्टियां भेजने के लिए श्रेष्ठ कार्यों का आरुप (format) www.indiaurbanportal.in और www.niua.org से डाउनलोड किया जा सकता है।

## भावी घटनाएं

### पर्ल पर राष्ट्रीय कार्यशाला

6 नवम्बर 2009, हैदराबाद

### जे.एन.एन.यू.आर.एम. प्रवेशिकाएं

शहरी विकास मंत्रालय ने जे.एन.एन.यू.आर.एम के अंतर्गत अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों के लिए निम्नलिखित प्रवेशिकाओं का चयन किया:

**अनिवार्य सुधार**

**यू.एल.बी. स्तर के सुधार**

- ई-शासन
- म्युनिसिपल लेखाकरण
- संपत्ति कर

**राज्य स्तर के सुधार**

- औचित्य-पूर्ण स्टाम्प शुल्क
- समुदाय भागीदारी कानून
- जन-प्रकटन कानून

**वैकल्पिक सुधार**

- वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए उपनियमों में संशोधन
- भूमि और संपत्ति पंजीकरण की कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का आरंभ
- अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग के लिए उपनियम
- संरचनात्मक सुधार
- सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना
- अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन
- कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों में परिवर्तित करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक रुपरेखा का सरलीकरण करना।

ये प्रवेशिकाएं पर्ल वेबसाइट पर उपलब्ध है www.indiaurbanportal.in


**कार्यदल**

समन्वयक : विजय धर
संपादक : डा. राजेश चन्द्रा
हिंदी रुपांतर : पूनम मल्होत्रा
हिंदी टंकक : मीरा भागचंदानी
संपादकीय दल : पूर्णीमा सिंह, रुम्मानी सेन नीलांजना दास गुप्ता सुर
सलाहकार चेतन वैद्य



**राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान**
कोर ४ बी, प्रथम एवं द्वितीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली - ११०००३
फोनः ०११-२४६२७५४३फैक्स २४६१७५१३
ई मेलः niua@niua.org
पर्ल वेबसाइटः www.indiaurbanportal.in
रा.न.का.सं. की वेबसाइटः www.niua.org